(f) if so, the action taken on the request ; and

(g) the date by when alllottees successful in the draw of lots will be given actual possession of the flats in the Sidharth Extension or any other area in Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) and (b) No, Sir. A draw for allocation of Category II flats at Sidharth Extension was held on 7-7-82. Draw for allotment of specific flats has yet to be held.

(c) Yes, Sir.

(d) The land for construction of flats could not become available due to stay orders of the Court. Alternative land in the same area was located by DDA in June, 1985.

(e) Yes, Sir.

(f) 45 allottees have been accommodated on their requests in other colonies where the flats were available.

(g) 296 Category II MIG allottees are likely to be given possession of the flats by February, 1986 and the remaining by the end of December, 1986.

Loss due to Floods in Tamil Nadu

2064. SHRI M. KALYANA SUNDARAM : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the month in which the Central team visited Tamil Nadu to evaluate the damages due to recent floods ;

(b) the details of long-term and short-term relief evaluated by the team ;

(c) the details of the demands received from the Tamil Nadu Government for Central assistance; and

(d) the details of the relief already sanctioned and proposed to be sanctioned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) A Central Team visited the cyclone and flood-affected areas of Tamil Nadu during 22nd to 25th November, 1985.

(b) The report of the Central Team is awaited.

(c) On the 22nd November, 1985, the State Government submitted a Memorandum to the Central Team asking for Central assistance of Rs. 12,549.76 lakhs. Subsequently on the 2nd December, 1985, the State Government submitted a supplementary Memorandum indicating the requirement of Central assistance at Rs. 18,733.18 lakhs.

(d) The Government of India released Central share of Margin Money amounting to Rs. 4.375 crores. Further assistance will be provided on the basis of the report of the Central Team and the recommendations of the High Level Committee on Relief.

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए नई नीति

2065. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई नई नीति बनाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यह योजना कब तक और किस प्रकार क्रियान्वित की जाएगी और इस संबंध में इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) राजस्थान के कितने आदिवासी जिलों और उनकी कितनी जनसंख्या

के इस योजना से लाभान्वित होने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आदिवासी उपयोजना जो 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है, का उद्देश्य व्यक्तिगत परिवार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आदिवासियों का विस्तृत विकास करना है। सातवीं योजना कार्यकारी दल ने जो योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, आदिवासी उप-योजना नीति की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप-योजना नीति के उद्देश्यों को पुनःनिर्धारित किया है । सातवी योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना नीति के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, लघु उद्योग इत्यादि के क्षेत्र में लाभान्वित होने वाले परिवारों के उत्पादकता स्तर को उठाने के लिए परिवारोन्मुखी लाभकारी कार्यक्रमों को चलाना।

(ii) जनजातियों के शोषण को समाप्त करना।

(iii) शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानव संसाधनों का विकास।

(iv) मूल संरचना विकास।

(v) संवेदनशील जनजाति क्षेत्रों और समूहों का विकास।

(vi) जनजाति क्षेत्रों के पर्यावरण का दर्जा बढ़ाना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 756 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता सहित लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था है।

प्रधान मंत्री के दौरे के बाद, आदिवासी उप-योजना नीति की कार्य प्रणाली का पुनर्रीक्षण किया गया तथा राज्य सरकारों को योजनाओं के विशेष तौर से परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के प्रभावशाली प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए कदम उठाने के लिए उचित रूप से निर्देश दिए गए हैं।

(ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में राजस्थान के दो पूर्ण जिले तथा तेरह आंशिक जिले आते हैं जिनकी जनजाति जनसंख्या लगभग 27.00 लाख है। सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,08,800 परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने का प्रस्ताव है। राजस्थान के लिए छठी योजना में 32.32 करोड़ रुपए के मुकाबले सातवीं योजना में 47.25 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता है।

पानी के टैंकर खरीदने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

2066. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पीने के पानी की समस्या हल करने के पेय जल के टैंकर खरीदने हेतु केन्द्र से हाल में कोई वित्तीय मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मदद दिए जाने की संभावना है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए पेयजल टैंकरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार को 100 पेयजल टैंकर खरीदने की अनुमति दे दी गई है और वास्तविक लागत केन्द्रीय सहायता में से मुहैया की जाएगी।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

2067. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ओपन कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की कोई योजना है; और